The 795th meeting of the State Expert Appraisal Committee (SEAC) was held on 21st May, 2025 under the Chairmanship of Shri Rakesh Kumar Shrivastava for the projects which are scheduled in the agenda. Following members attended the meeting in person or through video conferencing -

1. Shri Vijay Kumar Ahirwar, Member.
2. Dr. Rakesh Kumar Pandey, Member.
3. Dr. Pallavee Bhatnagar, Member.
4. Dr. Sunita Singh, Member.
5. Dr. Sushil Manderia, Member.
6. Shri A.A. Mishra, Member Secretary.

The Chairman welcomed all the members of the State Expert Appraisal Committee. After that agenda items- wise taken up for deliberations.

1. Case No P2/434/2024 SATENDRA SINGH, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 6.000 Hectare, Khasra No.- 51, in Village - KOTPARMAHANT -1 , Tehsil - Bareli, District - Raisen (MP), Maximum Production - 72000 cum per annum [477774] (Query Reply) (EIA)

Earlier this case was discussed in 762th A SEAC Meeting dated 02-06-2024 wherein following query was issued

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । प्रस्तावित खदान नर्मदा नदी क्षेत्र में स्थित है। गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के डाउन स्ट्रीम में 270 मी. पर मेजर रोड ब्रिज है। रेत की प्रस्तावित उत्खनन मात्रा भी अधिक है, जो 72000 घनमीटर/वर्ष है। अतः समिति का मत है कि प्रस्तावित खदान में रेत उत्खनन के संबंध में ब्रिज कार्पोरेशन के सक्षम अधिकारी से अनापत्ति पत्र प्राप्त किये जाने के उपरांत ही खदान के के उत्खनन के संबंध में विचार किया जाना उचित होगा।

ADS- परियोजना प्रस्तावक खदान के पास स्थित मेजर रोड ब्रिज के संबंध में ब्रिज कार्पोरेशन के सक्षम अधिकारी से अनापत्ति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

Hence this case is scheduled for query reply presentation.

The case is presented by the Environmental Consultant Shri Vidya Bhusan Trivedi, M/s. Cognizance Research India Pvt. Ltd., along with PP for M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd., Shri Arjun Shrivastava, (Authorized Person).

PP stated that the Mining Officer letter & Madhya Pradesh Lok Nirman Bhibhag Letter regarding Bridge.

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, भोपाल का पत्र क्रमांक 809 दिनांक 24/04/2025 प्रस्तुत किया पत्र में लेख है कि खसरा क्रमांक 51, रकबा 6.0 हे. क्षेत्र पर रेत खदान कोटपारमहंत–1, तहसील बरेली, जिला रायसेन पर खनिज रेत खदान स्वीकृत है। उक्त खसरा के स्वीकृत क्षेत्र से नर्मदा नदी पुल की दूरी 500 मी. के अन्दर है जिसमें रेत उत्खनन में विभाग को आपत्ति है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में समिति ने निर्णय लिया कि पर्यावरणीय संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित नहीं किया जा सकता।

2. **Case No P2/425/2024 SATENDRA SINGH, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 10.000 Hectare, Khasra No.- 51, in Village - Kotparmahant अ, Tehsil - Bareli, District - Raisen (MP), Maximum Production - 120000 cum per annum [477786] (Query Reply) (EIA)**

Earlier this case was discussed in 762th A SEAC Meeting dated 02-06-2024 wherein following query was issued

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । प्रस्तावित खदान नर्मदा नदी क्षेत्र में स्थित है। गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के डाउन स्ट्रीम में 400 मी. पर मेजर रोड ब्रिज है। रेत की प्रस्तावित उत्खनन मात्रा भी अधिक है, जो 120000 घनमीटर/वर्ष है। अतः समिति का मत है कि प्रस्तावित खदान में रेत उत्खनन के संबंध में ब्रिज कार्पोरेशन के सक्षम अधिकारी से अनापत्ति पत्र प्राप्त किये जाने के उपरांत ही खदान के उत्खनन के संबंध में विचार किया जाना उचित होगा।

ADS- परियोजना प्रस्तावक खदान के पास स्थित मेजर रोड ब्रिज के संबंध में ब्रिज कार्पोरेशन के सक्षम अधिकारी से अनापत्ति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

Hence this case is scheduled for query reply presentation.

The case is presented by the Environmental Consultant Shri Vidya Bhusan Trivedi, M/s. Cognizance Research India Pvt. Ltd., along with PP for M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd., Shri Arjun Shrivastava, (Authorized Person). PP stated that the Mining Officer letter & Madhya Pradesh Lok Nirman Bhibhag Letter regarding Bridge.

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, भोपाल का पत्र क्रमांक 806 दिनांक 24/04/2025 प्रस्तुत किया पत्र में लेख है कि खसरा क्रमांक 51, रकबा 10.0 हे. क्षेत्र पर रेत खदान कोटपारमहंत–ए, तहसील बरेली, जिला रायसेन पर खनिज रेत खदान स्वीकृत है। उक्त खसरा के स्वीकृत क्षेत्र से नर्मदा नदी पुल की दूरी 500 मी. से अधिक है जिसमें रेत उत्खनन में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि अपस्ट्रीम दिशा में 471 मी. पर एक मेजर रोडब्रिज (NH-19) स्थित है। अतः सेंड माईनिंग गाईडलाईन वर्ष 2016 एवं 2020 में निर्धारित दूरी छोड़ने पर रेत खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में समिति ने निर्णय लिया कि पर्यावरणीय संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित नहीं किया जा सकता।

3. Case No P2/479/2024 GAYAPRASAD ANJNE, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 6.110 Hectare, Khasra No.- 1005/1008, 442/1007/1, in Village - BHAMRAH, Tehsil - Manpur, District - Umaria (MP), Maximum Production - 109980 cum per annum [478445] (Query Reply) (EIA)

Earlier this case was discussed in 763th SEAC Meeting dated 04-06-2024 wherein following query was issued

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । एकल प्रमाण–पत्र में ईको सेंसेटिव जोन से दूरी स्पष्ट नहीं है । अतः संबंधित क्षेत्र के वन मण्डलाधिकारी से दूरी स्पष्ट कराई जावे ।

ADS एकल प्रमाण–पत्र में ईको सेंसेटिव जोन से दूरी स्पष्ट नहीं है। अतः वन मण्डलाधिकारी से दूरी स्पष्ट कराई जावे ।

Hence this case is scheduled for query reply presentation.

The case is presented by the Environmental Consultant Shri Vidya Bhusan Trivedi, M/s. Cognizance Research India Pvt. Ltd., along with PP for M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd., Shri Gaya Prasad Anjane, (Authorized Person). **PP submitted that the Mining Officer letter & Ekal Certificate And Forest Letter for ESZ.**

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय क्षेत्र संचालक, बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व, उमरिया म.प्र. का पत्र कमांक 1728 दिनांक 26/06/2024 प्रस्तुत किया पत्र में लेख है कि ग्राम भमरहा, तह. मानपुर, जिला उमरिया की शासकीय भूमि खसरा कमांक 1005/1008, 442/1007/1 कुल रकबा 6.11 हे. में आवेदित स्थल बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व की ईको सेंसिटिव जोन व बफर सीमा से दूरी 1.706 कि.मी. दर्शित है, वहीं दूरी ईको सेंसिटिव जोन हेतु भी दूरी 1.706 कि.मी. मान्य है।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि **-Bandhavgarh National Park and Panpatha Wildlife Sanctuary ESZ, vide notified by S.O. 4027 (E) December 14, 2016 MOEF&CC,** में ईको सेंसिटिव जोन की दूरी 02 कि.मी. तक दर्शाई गई है अतः समिति का निर्णय है कि उक्त संबंध में परियोजना प्रस्तावक कार्यालय क्षेत्र संचालक, बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व, उमरिया से ईको सेंसिटिव जोन से आवेदित रेत खनन स्थल की दूरी का उल्लेख करते हुये स्पष्ट अभिमत प्राप्त करें, तत्पश्चात पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा।

4. Case No P2/480/2024 GAYAPRASAD ANJNE, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 2.024 Hectare, Khasra No.- 344, in Village - KHAIRBHAR-1 , Tehsil - Chandia, District - Umaria (MP), Maximum Production - 36432 cum per annum [478702] (Query Reply) (EIA)

Earlier this case was discussed in 764th A SEAC Meeting dated 05-06-2024 wherein following query was issued

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनवरी 2024 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई। खनन क्षेत्र कुल 3.414 हेक्टेयर प्रस्तावित है । खनन क्षेत्र के उत्तर दिशा में अपस्ट्रीम पर 292 मीटर पर जल संरचना एवं ब्रिज है। लोक निर्माण विभाग के पत्र क्रमांक 213 दिनांक 24/05/2024 में स्थल विशेष का विवरण नहीं दिया गया है अर्थात् किस खसरा नम्बर से संबंधित है,स्पष्ट नहीं है ।

ADS उपरोक्तानुसार।

Hence this case is scheduled for query reply presentation.

The case is presented by the Environmental Consultant Shri Vidya Bhusan Trivedi, M/s. Cognizance Research India Pvt. Ltd., along with PP for M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd., Shri Gaya Prasad Anjane, (Authorized Person). PP stated that the Mining Officer letter & Bridge Corporation Letter Regarding Bridge & Revised Surface Map

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रीवा का पत्र क्रमांक 641 दिनांक 29/07/2024 प्रस्तुत किया पत्र में लेख है कि *"पुल एवं पहुॅच मार्ग के दोनों तरफ 500 मी. अपस्ट्रीम एवं 500 मी. डाउनस्ट्रीम की दूरी में सेंड एण्ड ग्रेवल की खुदाई की जाती है तो इस कार्यालय को कोई अपत्ति नहीं होगी। यदि पुल एवं पहुॅच मार्ग के दोनों तरफ 500 मी. अपस्ट्रीम एवं 500 मी. डाउनस्ट्रीम की दूरी में रेत की खुदाई की जाती है तो पुल एवं पहुॅच मार्ग के किसी भी प्रकार की क्षति होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी एवं संबंधित की होगी ।"*

समिति ने प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि स्टापडेम के स्पॉन (104मी.) को दृष्टिगत रखते हुये पॉच गुना स्पान छोड़ने पर कुल प्रस्तावित 2.024 हेक्टेयर में से गैर खनन क्षेत्र 1.074 हे. एवं खनन हेतु मात्र 0.95 हे. क्षेत्र उपलब्ध होता है।

समिति द्वारा उपलब्ध खनन क्षेत्र एवं डीएसआर में उल्लेखित मात्रा के आधार पर 28,500 घ.मी. रेत उत्खनन हेतु अनुशंसा की जाती है।

The EMP and other submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC subject to the following special conditions in addition to the standard conditions at annexure 'B':

1. Production as per approved mine plan with quantity not exceeding for Sand 28,500 cum per annum.

2. Mining operation shall be carried out as per given below proposed actual mining area with justifying sand quantity considering depth mentioned in the DSR as well as mining plan.

Area (Ha)	Minable Area	Area (m^2)	Thickness of Mineral (in M)	Volume (in m^3)	Proposed Production of Sand (in m^3
2.024	0.95	9500	3.0	28,500	28,500
TOTAL					28,500

3. A budgetary provision for Environmental Management Plan of Rs. 5,72,500 as capital and Rs 3,80,300 as recurring has proposed by PP.

4. As proposed, a minimum of 1500 Plants shall be planted During the Study Period in barrier zone, and evacuation road and distributed to villagers through Gram Panchayat as per the submitted plantation scheme.

5. CER ACTION PLAN

S. No.	Activity	Capital Cost (in Rs.)
1.	ग्राम खैरभार में रोड लाईट के लिए ।	20,000
2.	खैरभार गाँव में सामाजिक कार्य के रूप में पंजीकृत गौशाला के विकास के लिए।	30,000
3.	सी.ई.आर मद से 50,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम खैरभार के शासकीय प्राथमिक भााला के बैंक खाते में शाला विकास कार्य हेतु भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	50,000
Total		1,00,000

5. Case No P2/467/2024 HARISHANKAR SHUKLA, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 6.000 Hectare, Khasra No.- 223/551, in Village - SEMARPAKHA , Tehsil - Jaisinghnagar, District - Shahdol (MP), Maximum Production - 108000 cum per annum [478782] (Query Reply) (EIA)

Earlier this case was discussed in 764th A SEAC Meeting dated 05-06-2024 wherein following query was issued

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कुल 6.0 हेक्टेयर प्रस्तावित है । खनन क्षेत्र के दक्षिण दिशा में 600 मीटर की दूरी पर ब्रिज है । अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ''ब्रिज, रपटा, पुल, पुलिया, इन्टेक वेल, स्टापडेम, स्थाई एवं अस्थाई संरचना संबंधित विभाग/संस्था जो संरचना की देखरेख व रख–रखाव की जिम्मेदार है, अर्थात् संधारण किया जा रहा है, संबंधित से ब्रिज, रपटा, पुल, पुलिया, इन्टेक वेल, स्टापडेम, स्थाई एवं अस्थाई संरचना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये कितनी दूर तक अपस्ट्रीम एवं डाऊनस्ट्रीम में रेत खनन को प्रतिबंधित किया जावे'', स्पष्ट अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे ।

ADS उपरोक्तानुसार।

Hence this case is scheduled for query reply presentation.

The case is presented by the Environmental Consultant Shri Vidya Bhusan Trivedi, M/s. Cognizance Research India Pvt. Ltd., along with Shri Rahul Shandilya , (Mining Officer) on-line presented that the Mining Officer letter & Bridge Corporation Letter Regarding Bridge.

During presentation PP submitted Mining Officer letter No. 19/Khanij/2025/490, Shahdol, Dated 09.04.2025 & Bridge Corporation Letter No. 173/Anu. Li/2025, Shahdol, Dated – 09.04.2025.

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण उप संभाग, शहडोल का पत्र कमांक 173 दिनांक 09/04/2025 द्वारा कार्यपालन यंत्री, एवं सहायक खनिज अधिकारी, शहडोल को निर्देशित पत्र प्रस्तुत किया पत्र में लेख है कि *"ग्राम सेमरपाखा के पासे सोन पुर पोड़ी राजघाट पुल के नजदीक जो रेत खदान का आवंटन किया जा रहा है उक्त निर्मित पुल के 500 मी. अपस्ट्रीम एवं 500 मी. डाउनस्ट्रीम में रेत का उत्खनन नहीं किये जाने हेतु सहायक खनिज अधिकारी, शहडोल को पत्र जारी करने का अनुरोध है।"*

समिति ने प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि डाउनस्ट्रीम दिशा में 600 मी. पर दक्षिण दिशा में एक रोडब्रिज (स्पॉन 350 मी.) स्थित है। अतः सेंड माईनिंग गाईडलाईन वर्ष 2016 एवं 2020 में निर्धारित दूरी छोड़ने पर रेत खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में समिति ने निर्णय लिया कि पर्यावरणीय संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित नहीं किया जा सकता है।

6. **Case No P2/436/2024 SATENDRA SINGH, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 4.000 Hectare, Khasra No.- 735, in Village - BORAS-1 , Tehsil - Udaipura, District - Raisen (MP), Maximum Production - 48000 cum per annum [478442] (Query Reply) (EIA)**

Earlier this case was discussed in 764th A SEAC Meeting dated 05-06-2024 wherein following query was issued

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अप्रैल 2024 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई खनन क्षेत्र कुल 4.0 हेक्टेयर प्रस्तावित है । खनन क्षेत्र के उत्तर दिशा में ब्रिज है । अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ''ब्रिज, रपटा, पुल, पुलिया, इन्टेक वेल, स्टापडेम, स्थाई एवं अस्थाई संरचना संबंधित विभाग/संस्था जो संरचना की देखरेख व रख–रखाव की जिम्मेदार है, अर्थात् संधारण किया जा रहा है, संबंधित से ब्रिज, रपटा, पुल, पुलिया, इन्टेक वेल, स्टापडेम, स्थाई एवं अस्थाई संरचना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये कितनी दूर तक अपस्ट्रीम एवं डाऊनस्ट्रीम में रेत खनन को प्रतिबंधित किया जावे'', स्पष्ट अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे ।

ADS उपरोक्तानुसार

Hence this case is scheduled for query reply presentation.

The case is presented by the Environmental Consultant Shri Vidya Bhusan Trivedi, M/s. Cognizance Research India Pvt. Ltd., along with PP for M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd., Shri Arjun Shrivastava, (Authorized Person). PP stated that the Mining Officer letter & Madhya Pradesh Lok Nirman Bhibhag Letter regarding Bridge.
During presentation PP submitted Mining Officer letter No. 80/Khanij/2025-26, Raisen, Dated 24.04.2025 & Bridge Corporation Letter No.808/Tak/NOC/2025, Bhopal, Dated – 24.04.2025 regarding Bridge.

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, भोपाल का पत्र कमांक 808 दिनांक 24/04/2025 द्वारा प्रस्तुत पत्र में लेख है कि *"ग्राम बोरस के तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन के खसरा कमांक 735, रकबा 4.0 हे. पर बोरस–1 खनिज रेत खदान स्वीकृत है उक्त खसरा के स्वीकृत क्षेत्र से नर्मदा नदी पुल की दूरी 500 मी. से अधिक है जिसमें रेत उत्खनन में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।"*

समिति ने प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि पश्चिम दिशा में नर्मदा रोडब्रिज (NH-44) 500 मी. की दूरी पर स्थित है, रोडब्रिज का स्पॉन 350 मी. है, अतः सेंड माईनिंग गाईडलाईन वर्ष 2016 एवं 2020 में निर्धारित दूरी छोड़ने पर रेत खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में समिति ने निर्णय लिया कि पर्यावरणीय संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित नहीं किया जा सकता है।

7. **Case No P2/447/2024 SHASHIKANT TIWARI, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 17.210 Hectare, Khasra No.- 560, in Village - Parsana, Tehsil - Biaora, District - Rajgarh (MP), Maximum Production - 16800 cum per annum [479115] (Query Reply) (EIA)**

Earlier this case was discussed in 765th A SEAC Meeting dated 07-06-2024 wherein following query was issued

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कुल 17.210 हेक्टेयर पार्वती नदी पर प्रस्तावित है, खनन क्षेत्र 2 हिस्सों में है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिसम्बर 2023 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें पूरा खनन क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है, परियोजना प्रस्तावक खनिज अधिकारी से ''वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षो में कितनी रेत ई. सी. के विरूद्व निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार'' पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे । ADS

Hence this case is scheduled for query reply presentation.

The case is presented by the Environmental Consultant Shri Vidya Bhusan Trivedi, M/s. Cognizance Research India Pvt. Ltd., along with PP for M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd., Shri Shashikant Tiwari, (Authorized Person). PP stated that the Mining Officer letter & Geo Tagged Photographs.

पत्र में उल्लेख किया है कि "उक्त खदान वर्ष 2020 से संचालित नहीं है। पारसाना` *खदान का मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण में खनन खेत्र में वर्तमान में पानी भरा हुआ पाया गया है। जियोटेग फोटोग्राफ लिये गये। 16,800 घन मी. खनन योग्य मात्रा अनुमोदित खनन योजना में दर्शाई गई है। जियोटेग फोटोग्राफ संलग्न है।"*

समिति ने प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–राजगढ़ के पत्र में मौका निरीक्षण में खनन खेत्र में वर्तमान में पानी भरा हुआ पाया गया है एवं संलग्न जियोटेग फोटोग्राफ भी स्पष्ट नहीं हैं। लीज एरिया दो भागों में है पश्चिमी भाग से एक पक्का रोडब्रिज लीज क्षेत्र के अत्यंत समीप है एवं अन्य दूसरा भाग पूर्वी दिशा में 1.68 कि.मी. दूर है। परियोजना प्रसवक के पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि पूर्वी दिशा में स्थित लीज क्षेत्र में पानी में डूबा हुआ क्षेत्र छोड़कर 7.21 हे. में से मात्र 4.2 हे. में खनन कार्य प्रस्तावित है। समिति द्वारा डीएसआर में उल्लेखित मात्रा के आधार पर 16,800 घ.मी. रेत उत्खनन हेतु अनुशंसा की जाती है।

The EMP and other submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case

for grant of prior EC subject to the following special conditions in addition to the standard conditions at annexure 'B':

1. Production as per approved mine plan with quantity not exceeding for Sand 16,800 cum per annum.

2. Mining operation shall be carried out as per given below proposed actual mining area with justifying sand quantity considering depth mentioned in the DSR as well as mining plan.

Area (Ha)	Minable Area	Area (m^2)	Thickness of Mineral (in M)	Volume (in m^3)	Proposed Production of Sand (in m^3
7.00	4.20	42000	0.4	16,800	16,800
TOTAL					16,800

3. A budgetary provision for Environmental Management Plan of Rs. 6,60,500 as capital and Rs. 2,88,100 as recurring has proposed by PP.

4. As proposed, a minimum of 5100 Plants shall be planted During the Study Period in barrier zone, and evacuation road and distributed to villagers through Gram Panchayat as per the submitted plantation scheme.

5. CER ACTION PLAN

S. No.	Activity	Capital Cost (in Rs.)
1 .	सी.ई.आर मद से 60,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम परसाना के शासकीय प्राथमिक शाला के बैंक खाते में शाला विकास कार्य हेतु भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	60,000
Total		60,000

8. **Case No P2/439/2024 SATENDRA SINGH, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 3.300 Hectare, Khasra No.- 187, in Village - KOTPARMAHANT-2 , Tehsil - Bareli, District - Raisen (MP), Maximum Production - 39600 cum per annum [479171] (Query Reply) (EIA)**

Earlier this case was discussed in 765th SEAC Meeting dated 07-06-2024 wherein following query was issued

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कुल 3.300 हेक्टेयर नर्मदा पर प्रस्तावित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिसम्बर 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें पश्चिम दिशा में अपस्टीम पर 755 मीटर की दूरी पर ब्रिज है । अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा ''खनन क्षेत्र में ब्रिज, स्थाई एवं अस्थाई संरचना संबंधित विभाग/संस्था जो संरचना की देखरेख व रख–रखाव की जिम्मेदार है, अर्थात् संधारण किया जा रहा है, संबंधित से ब्रिज, स्थाई एवं अस्थाई संरचना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये कितनी दूर तक अपस्ट्रीम एवं डाऊन स्ट्रीम में रेत खनन को प्रतिबंधित किया जावे, स्पष्ट अभिमत'' प्राप्त करने के पश्चात् समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। ADS

Hence this case is scheduled for query reply presentation.

The case is presented by the Environmental Consultant Shri Vidya Bhusan Trivedi, M/s. Cognizance Research India Pvt. Ltd., along with PP for M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd., Shri Arjun Shrivastava, (Authorized Person). PP stated that the Mining Officer letter & Madhya Pradesh Lok Nirman Bhibhag Letter regarding Bridge.

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, भोपाल का पत्र क्रमांक 807 दिनांक 24/04/2025 द्वारा प्रस्तुत पत्र में लेख है कि *"उपरोक्त विषयांतर्गत ग्राम कोटपारमहंत के खसरा क्रमांक 187, रकबा 3.300 हे. क्षेत्र पर रेत खदान कोटपारमहंत–2, तहसील बरेली, जिला रायसेन पर खनिज रेत खदान स्वीकृत है उक्त खसरा के स्वीकृत क्षेत्र से नर्मदा नदी पुल की दूरी 500 मी. से अधिक है जिसमें रेत उत्खनन में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। "*

समिति ने प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि पश्चिम दिशा में नर्मदा रोडब्रिज (NH-19) 500 मी. की दूरी पर स्थित है, रोडब्रिज का स्पॉन 450 मी. है, अतः सेंड माईनिंग गाईडलाईन वर्ष 2016 एवं 2020 में निर्धारित दूरी छोड़ने पर रेत खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में समिति ने निर्णय लिया कि पर्यावरणीय संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित नहीं किया जा सकता।

9. Case No P2/1035/2025 Shri Mahendra Singh Chouhan, Ex. En. C Narmada Valley Development Authority, Lower Narmada Projects, Narmada Bhavan, B-G, Scheme no 74-C, Vijay Nagar – Indore, Distt.- Indore (M.P.) – Pin – 452010. Prior Environment Clearance for Sondwa Micro Lift Irrigation Project, The Sondwa Micro Lift Irrigation Project has been conceived to cater irrigation water to about 55,013 Ha. of CCA in Alirajpur district. A Total of 169 villages of Alirajpur district will be benefited by this scheme. [519572] (Referred Back by SEIAA) (TOR).

Earlier in the SEAC meeting 775th Dated 21/02/2025 TOR was recommended. SEIAA vide 879th meeting dated 18/03/2025 case sent back to SEAC for re-examination with following observation.

15. **Case No. P2/1035/25** Prior Environment Clearance for Sondwa Micro Lift Irrigation Project, 55,013 Ha. of CCA in Alirajpur district. A Total of 169 villages of Alirajpur district will be benefited by this scheme by, Executive Engineer, CE NVDA Lower Narmada Projects Indore, Lower Narmada Projects, Narmada Bhavan, B-G, Scheme no 74-C, Vijay Nagar – Indore, Distt.- Indore (M.P.)-452010 Email: cenvda.alirajpur@gmail.com ToR Cat. - 1(c) River Valley/Irrigation Projects Proposal No. SIA/MP/RIV/519572/2025.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 775 वी बैठक दिनांक 21.02.24 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–डी) सहित टॉर जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड KML फाईल के आधार पर प्रस्तावित परियोजना से अंतर्राज्यीय गुजरात सीमा की दूरी 0 मीटर है, जबकि कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग अलीराजपुर द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड पत्र अनुसार अंतर्राज्यीय सीमा की दूरी 50 किलोमीटर होना बताया गया है। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 25.06.2014 अनुसार 1(c) श्रेणी की परियोजनाओं में यदि अंतर्राज्यीय सीमा 10 किलोमीटर के अंदर स्थित है तो प्रकरण ए–श्रेणी के अंतर्गत होने के कारण भारत सरकार द्वारा निर्णय किया जायेगा।

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

The case presented by the Env. Consultant Mr. Ravindra Bhatiya On-line, M/s. R. S. Envirolinks Technologies Pvt. Ltd., Gurugram and authorized representative of PP Shri Pradeep, E.E. wherein PP submitted Project was recommended by SEAC for issue of TOR in its 775th meeting held on 21/02/2025. SEIAA during its 879th meeting held on 18/03/2025 have reviewed the SEAC recommendation and noted that the proposed scheme is at a distance of 0 m from interstate boundary with Gujarat, therefore, as per EIA notification dated 25/06/2014 (amendment), item 1(c), schemes falling within 10 Km of interstate boundary are Category A projects and therefore to be appraised by Government of India.

PP further submitted that:

- This is a Micro Irrigation Project designed to provide irrigation facilities to the water-scare areas in lower reaches of Naramda basin, in Alirajpur district..
- No dam will be constructed, therefore no submergence; as water storage requirement is not envisaged.
- Project consists of construction of pumphouses, distribution chambers and laying of underground pipelines.
- Water will be lifted from Hathini river, a right bank tributary of Narmada rver and distribution through a pressurized piped system to cultivators for irrigation during Rabi season.
- The project is designed to irrigate a total of 55,013 ha of CCA on right bank of Naramda river covering 169 villages of 5 tehsils of Alirajpur district.
- Entire project area including lifting location, distribution network and entire command falls in Alirajpur district .
- The EIA notification of September 2006 with its amendment dated 25/06/2014 (referred by SEIAA) describes Category 1(c) as:

	Project	Category A	Category B	Conditions
"1(c)	(i) River Valley projects	(i) ≥ 50 MW hydroelectric power generation;	(i) ≤ 50 MW ≥ 25 MW hydroelectric power generation;	General Condition shall apply. Note:- Category 'B' river valley projects falling in more than one state shall be appraised at the central Government Level."
	(ii) Irrigation projects	(ii) ≥ 10,000 ha of culturable command area.	(ii) < 10,000 ha > 2000 ha of culturable command area.	

Any project or activity specified in Category 'B' will be appraised at the Central Level as Category 'A', **if located in whole or in part within 5 km from the boundary of:** (i) Protected Areas notified under the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972); (ii) Critically Polluted areas as identified by the Central Pollution Control Board constituted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) from time to time; (iii) Eco-sensitive areas as notified under sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, and **(iv) inter-State boundaries and international boundaries**; **provided that for** River Valley Projects **specified in item 1(c),** Thermal Power Plants specified in item 1(d), Industrial Estates/ parks/complexes/areas, export processing zones (EPZ), Special Economic Zones (SEZs), biotech parks, leather complexes specified in item 7 (c) and common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs) specified in item 7 (d), **the**

appraisal shall be made at Central level even if located within 10 km.

- Original EIA notification of September 2006, mentions item 1(c) as ”River Valley Projects”, however, 2014 amendment has split the category 1(c) in two parts viz.
  (i) River Valley Projects and
  (ii) Irrigation Projects
- Original EIA notification of September 2006, has no distinction in different types of projects based on distance from state boundary i.e. all the projects within 10 Km of state boundary were to be categorised as A and appraised at centre.
- 2014 amendment has split category 1 (c) in two parts, where river valley projects will be considered as Category “A” if fall within 10 Km of state boundary, however, irrigation projects will be categorised as “A”, if fall within 5 Km of the state boundary.
- Main project components i.e. pumphouses, distribution chambers and rising main are all more than 5 Km away
- Shortest distance from state boundary of DC1 is 7 Km.
- Beyond this only distribution network of HDPE pipes will carry water up to 2.5 ha chak
- Command area comprises only of agricultural zones receiving water, with no construction or physical structures situated near or along the state boundary.
- No land acquisition for the project is envisaged within 5 Km of interstate boundary.
- General Conditions mention that:

  Provided further that the requirement regarding distance of 5 km or 10 km, as the case may be, of the inter-State boundaries can be reduced or completely done away with by an agreement between the respective States or the Union Territories sharing the common boundary in case the activity does not fall within 5 km or 10 km, as the case may be of the areas mentioned at item (i), (ii) and (iii) above.”

- Narmada Water Disputes Tribunal (NWDT), through its award dated 12 December 1979, allocated the waters of the Narmada River as follows:
  - **Madhya Pradesh:** 22,511 MCM (18.25 MAF),
  - **Maharashtra:** 308.37 MCM (0.25 MAF),
  - **Gujarat:** 11,101.32 MCM (9 MAF), and
  - **Rajasthan:** 616.74 MCM (0.5 MAF).

- This allocation has become final and binding for the respective states.

  Subsequently, in accordance with the decision of the Tribunal, the Narmada Control Authority (NCA) was established as the implementing agency for its directions and decisions. The Authority began functioning from 20 December 1980. It is a corporate body consisting of representatives from the four states — Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Rajasthan — and the Government of India.

- In the judgment of the Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Narmada Bachao Andolan vs. Union of India and Others dated 18/10/2000, it is mentioned that the Chief Ministers of Gujarat, Maharashtra, and Madhya Pradesh reached an agreement on the use of Narmada water.
- This is a public interest project and farmers need water in that area
- Being a lift irrigation scheme, without any dam/submergence; no significant land requirement, therefore No R&R issues; and minimal environmental impacts
- Already substantial time has been lost waiting for the TOR, a fresh application to center for TOR will delay the project further.
- Therefore, it is requested that kindly issue the TOR so that project can complete environment clearance process without any further delay.

In view of above facts as the project is maintaining desired distance from inter state boundaries to be considered as category B. However in such projects the PP must ensure to make available water for public utilities for the population residing near inter state boundaries. In no case the population at the out skrit of the project and within state boundary shall be deprived of water supply, irrigation of agriculture land etc.

Hence, standby earlier recommendation as made in 775th Dated 21/02/2025 for TOR.

10. **Case No P2/1124/2024 Shri OP Kriplani, Director, M/s Asnani Builders and Developers E-7/659 Arera Colony, Near P.N.B Bank Bhopal, (M.P.) - 462011.Prior Environment Clearance forProposed "Aashima Anupama City Phase II" Development of Plotted Housing (Residential flat) at Khasra no. 129/4, 129/9, 130/1, 131/1/1, 131/2, 131/3/1, 131/4/2, 132/1/5, 133, 134, 135, 136, 137/1, 137/2, 138/1, 138/2, 139/1, 139/2 140 at Village –Katara, Tehsil – Kolar, District – Bhopal, (M.P.), Total Plot Area –59,789.72 SQM (14.77 acre). Built up Area – 71482.55 sq mt.,Cat. - 8(a). Building and Construction projects.SIA/MP/INFRA2/522930/2024.**

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed "Aashima Anupama City Phase II" Development of Plotted Housing (Residential flat) at Khasra no. 129/4, 129/9, 130/1, 131/1/1, 131/2, 131/3/1, 131/4/2, 132/1/5, 133, 134, 135, 136, 137/1, 137/2, 138/1, 138/2, 139/1, 139/2 140 at Village –Katara, Tehsil – Kolar, District – Bhopal, (M.P.), Total Plot Area – 59,789.72 SQM (14.77 acre). Built up Area – 71482.55 sq mt..

Earlier, in the SEAC meeting 779th Dated 26.03.2025 after presentation committee aked PP to submit following information for further consideration of the project:

1. Protection plan for a stream passing along the boundary of the project site.
2. Revised STP proposal.
3. On the Google map it reveals that some sheds exist at project site, please provide details of the same with photographs.
4. Other options for green area enhancement in the project area.
5. Revised Plantation scheme and CER plan as suggested by committee.
6. Details regarding water supply, waste handling during construction period.
7. Quantity of water requirement that can be met from recycling of treated waste water and from water harvesting.
8. Impact of the project on the Ground Water.
9. Provisions made to avoid flooding of the area , details of the drainage facilities provided .
10. Measures proposed to be undertaken during deployment of construction labourers that may lead to unsanitary conditions nearby project site.
11. On-site facilities for the collection, treatment and safe disposal of sewage, treatment capacity, recycling and disposal.
12. Details of duel plunbing system to ensure use of treated sewage for flushing of toilets and any other use.
13. Proposal for tree plantation, land scaping, creation of water body etc.

14. Details of background air quality levels with predicted values taking into account the increased traffic generation due to proposed construction.
15. Details of internal roads, bicycle tracks, pedestrian path ways, foot paths etc. with area covered.
16. Impact of DG sets and other equipments on noise levels and vibration in and AAQ around the project site.
17. Details of energy conservation measures in the selction of building materials and their energy efficiency.
18. Transport and handling of materials during construction may result in pollution & public nuisance, proposed measures to minimize the impacts.
19. Methods of collection, segregation and disposal of the garbage generated during the construction and operation phases of the project.
20. Energy consumption assume per square feet of buit-up area & measures to minimize the same.
21. Precutions & safety measures proposed to mange fire hazards.
22. Rate of air infilteration into the building & its mitigating measures.

The EMP has to covered mitigation measures for above activites to be undertaken during construction and operation to minimized adverse environmental impacts as a result of project activities along with environmental monitoring plan.

In response to above queries, PP presented the query reply in the SEAC meeting 795th dated 21.05.2025. The query reply was presented by PP's Authorized Representative Shri Sumit Dhankani and Env Consultant Ms. Rashmi Saraswat and Shri Varun Bhardwaj, M/s Zenith Environment Consultancy, and Noida (U.P.)Wherein PP subnmitted point-wise replies.

- We have given specified set back from water body as required by T&CP based on MPBVR (Madhya Pradesh Bhumi Vikas Rule) accordingly we have obtained layout approval from concerned department.
- Sewage Generation & Treatment -The project is generating approx. 401.28 KLD of Sewage. The Sewage is being treated in the STP of capacity 440 KLD provided within the complex generating 321.02 KLD of recoverable water from STP which will be recycled & reused for various purposes such as Flushing, Horticulture etc.
- At project site there are two temporary sheds exist on site.
    1. Shed = 16*18mt (23° 10'59.46″N 77°29′04.04"E, It's a temporary site office.
    2. shed =2*3mt. (23°10'59.71"N 77^{0}28'59.11″E), It is guard rest room.

- Total area=59789.72 sqmt.
    1. Required Green Area as per MPBVR@10% of total area= 5978.972sqmt.

2. Additional green area=2990.67sqmt.
3. Total green area =8969.65 sqmt.

- PP also submitted revised Plantation scheme and revised CER, revised water supply details, Water Balance Diagram (Primary Season),Impact of the Project on Ground Water, Rain Water Harvesting Calculation, Provisions made to avoid flooding of the area, details of the drainage facilities , Details of dual plumbing system to ensure use of treated sewage for flushing of toilets and any other use. land scaping, creation of water body etc.
- PP has obtained CTE from MPPCB for this project vide letter no. 61614 dated 22.01.2025.

After presentation and submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case was recommended for grant of "**Prior Environment Clearance for Proposed "Aashima Anupama City Phase Ii" Development of Plotted Housing (Residential Flat) at Khasra No. - 129/4, 129/9, 130/1, 131/1/1, 131/2, 131/3/1, 131/4/2, 132/1/5, 133, 134, 135, 136, 137/1, 137/2, 138/1,138/2, 139/1, 139/2 140 at Village –Katara, Tehsil – Kolar, District – Bhopal, (M.P.), Total Project Area –59,800 Sqm. (5.98 Ha.) Built up Area – 71,482.55 sq mt., Cat. - 8(a).**

subject to the following special conditions:

I. Statutory Compliance

i. The project proponent shall obtain all necessary clearance/permission from all relevant agencies including town planning authority before commencement of work. All the construction shall be done in accordance with the local building byelaws.

ii. The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of building due to earthquakes, adequacy of firefighting equipment etc as per National Building code including protection measures from lightening etc.

iii. The project proponent shall obtain Consent to Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the MPPCB, Bhopal.

iv. The project proponent shall obtain the necessary permission for drawl of ground water/surface water required for the project from the competent authority.

v. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.

vi. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, and Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.

vii. The provisions for the solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, and the Plastics Waste (Management) Rules, 2016 shall be followed.

viii. The project proponent shall follow the ECBC/ECBC-R prescribed by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power Strictly.

ix. The project area shall be secure through boundary wall and excavated top soil shall not be used in filling of low lying area. The top soil shall be used for greenery development.

x. Protection plan shall be implemented for the stream passing along the boundary of the project site, as required by T&CP based on MPBVR (Madhya Pradesh Bhumi Vikas Rule) with protection measures to maintain the natural flow, course of stream from environment point of view.

II. Air Quality Monitoring and preservation

i. Notification GSR 94(E) dated: 25/1/2018 MoEF& CC regarding Mandatory implementation of Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition Activities for project requiring Environmental Clearance shall be complied with.

ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.

iii. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released covering upwind and downwind directions during the construction period.

iv. 01 Diesel power generating sets 250 kVA is proposed as source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Use of low sulphur diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board.

v. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall

include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking wills all around the site plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, Murram and other construction materials prone to causing dust polluting at the site as well as taking out debris from the site.

vi. Sand, Murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution.

vii. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.

viii. Unpaved surface and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.

ix. All construction and demolition debris shall be stored at the site (are not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.

x. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.

xi. The gaseous emission from DG sets 250 kVA * 01 nos. shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.

xii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

III. Water quality monitoring and preservation

i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.

ii. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible Minimum cutting and filling should be done.

iii. The total water requirement during operation phase is 462.6 KLD out of which 306.60 KLD is fresh water requirement and 321.02 KLD will be the total recycled water generated, out of which 156 KLD recycled water will be used for flushing and 26.91 KLD water will be used for horticulture.

iv. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring reports.

v. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.

vi. At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be previous. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as previous surface.

vii. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.

viii. Use of water saving devices/fixtures (Viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan.

ix. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.

x. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.

xi. The local bye-law construction on rain water harvesting should be followed. If local by-law provision is not available, adequate provisions for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building bylaws, 2016. Rain water harvesting recharge pits/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.

xii. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meter of built up area and storage capacity of minimum one day of total fires water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority.

xiii. For rainwater harvesting, 18 recharge pits will be constructed for harvesting rain water. The total recharge capacity of these pits about 28.26 m3/hr .Mesh will be provided at the roof so that leaves or any other solid waste/debris will be prevented from entering the pit.

xiv. The RWH will be initially done only from the roof top. Runoff from green and other open areas will be done only after permission from CGWB.

xv. All recharge should be limited to shallow aquifer.

xvi. No ground water shall be used during construction phase of the project.

xvii. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering.

xviii. The quality of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The recorded shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring report.

xix. Sewage shall be treated in the MBBR based STP (Total Capacity **- 440** KLD in 02 parts at different locations). The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing. AC makes up water and gardening. As proposed, no treated water shall be disposed in to municipal drain.

xx. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.

xxi. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problems from STP.

xxii. Sludge from the onsite sewage treatment including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Control Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013.

IV. **Noise monitoring and prevention**

i. Ambient noise levels shall conform to residential area/commercial area/industrial area/silence zone both during day and night as per Noise Pollution (Control and Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitoring during construction phase. Adequate measures shall be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB/SPCB.

ii. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer of the Ministry as a part of six-monthly compliance report.

iii. Acoustic enclosures for DG sets, noise barriers for ground run bays, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact due to ground sources.

V. Energy Conservation measures.

i. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured, Building in the State which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.

ii. Outdoor and common area lighting shall be LED.

iii. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.

iv. Energy Conservation measures like installation of CFls/LED's for the lighting the area outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning.

v. Solar, wind or other renewable energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level /local building bye-laws requirement, which is higher.

vi. Solar power shall be used for lighting in the apartment to reduce the power load on grid. Separate electric meter shall be installed for solar power. Solar water heating shall be provided to meet 20% of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building bye-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.

VI. Waste Management

i. Total waste 1747.494 Kg/day, this consist all types of wastes (as Organic waste 1048.49 Kg/day and non- organic waste 698.99 Kg/day), and these all type of waste shall be treated/ disposed off as per provision made in the MSW Rules 2016.

ii. A certificate from the competent authority handling municipal solid wastes, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the MSW generated from project shall be obtained.

iii. Disposal of muck during construction phase shall not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed taking

the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.

iv. Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste (0.4 ton/day) shall be segregated into wet garbage and inert materials.

v. All non-biodegradable waste shall be handed over the authorized recyclers for which a written tie up must be done with the authorized recyclers.

vi. Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the State Pollution Control Board.

vii. Use of environment friendly materials in bricks, blocks and other construction materials, shall be required for at least 20% of the construction materials quantity. These include fly ash brick, hollow bricks, AACs, Fly Ash Lime Gypsum block, compressed earth blocks and other environmental friendly materials.

viii. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003 and 25th January, 2016 Ready mixed concrete must be used in building construction.

ix. Any wastes from construction and demolition activities related thereto small be managed so as to strictly conform to the construction and Demolition Rules, 2016.

x. Used CFLs and TFLs should be properly collected and disposed off/sent for recycling as per the prevailing guidelines/rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination.

xi. Green engineered materials shall be preferred for contructions.

VII. **Green Cover**

i. Total 560 Tree shall be planted in the 15 % (8969.65 Sqmt.)of total plot area which is developed as greenbelt development as follows:

S.No.	Common Name	Biological Name
1.	Kachnar	Bauhinia variegata
2.	Amaltas	Cassia fistula
3.	Gursakri	Grewia hirsuta
4.	White Frangipani	Plumeria Alba
5.	Pride of India	Lagerstroemia speciosa

6.	Golden Rain Tree	Koelreuteria pediculate
7.	Flamboyant Flame Tree	Delonix regia
8.	Fishtail Palm	Caryota
9.	Whistling Pine	Casuarina equisetifolia
10.	Ashoka Tree	Saraca asoca
11.	Christmas tree	Araucaria columnaris
12.	Neem Tree	Azadirachta indica
13.	Badam Tree	Terminalia catappa
14.	Kathal Tree	Artocarpus heterophyllus
15.	Red frangipani	Plumeria Rubra
16.	Bauhinia variegata L.	Bauhinia
17.	Golden shower tree	Cassia Fistula
18.	Crepe-myrtle	Lagerstroemia Indica

ii. Not tree will be felled/transplant unless exigencies demand. Where absolute necessary, tree felling shall be with prior permission from the concerned regulatory authority. Old trees should be retained based on girth and age regulations as may be prescribed by the Forest Department. Plantations to be ensured species (cut) to species (Planted).

iii. A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land shall be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. The landscape planning should include plantation of native species, the species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and/or invasive species should not be used for landscaping.

iv. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, Compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.

v. Topsoil should be stripped to a depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. The soil should

be stack plied appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetations on site.

VIII **Transport**

i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public and private network. Road should be designed with due consideration for environment and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.

    a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic
    b. Traffic calming measures.
    c. Proper design of entry and exit points
    d. Parking norms as per local regulation

ii. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.

iii. Total proposed Parking's arrangement for 490 ECS (Plotted Parking–253 ECS, Open Parking–52 ECS & Phase c – 185 ECS).

iv. A detailed traffic management and traffic decongesting plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the road within a 05 Kms radius of the project as maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of the development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management and the PWD/competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.

v. The layout for parking the vehicles shall be in accordance with safety norms during turning and easy/safe entry and exit. The passage shall allow safe access to sewage cleaning machine, water supply tankers, Ambulance and Fire Tenders.

IX. Human health issues

i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.
ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.
iii. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implementation.
iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile, STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.
vi. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

X. EMP& Corporation Environment Responsibility

i. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated: 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.
ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The Environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balance and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions. The company shall have defined system of reporting infringements/deviation/ violation of the Environmental/forest/wildlife norms/conditions and/or shareholders/stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six monthly reports.
iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year

wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.

v. For Environment Management Plan PP has proposed Rs. 1.166 Cr as capital cost in Construction phase and Rs. 5.83 Lakh as recurring cost in Construction Phase 0.132 Lakh as capital cost in Operation Phase and 11.636 Lakh as recurring cost in Operation Phase for this project.

vi. For this project PP has proposed Rs. 32 Lakhs as Corporate Environment Responsibility (CER) for various activities as follows:

CER BUDGET	
Women Breast Cancer Champ in the Katara Twice a year	Rs. 20 Lakh
Development of Government middle school Barrai 1) 5 Kw Solar panel (6 Lakhs) 2) 2 Toilet for Girls Hostel (1 Lakh) 3) Distribution of Science equipment in Lab (5 Lakhs)	Rs. 12 Lakhs
Total	**Rs. 32 lakhs**
ALL CER Fund will Be Implemented within the first five years of the project.	

XI. Miscellaneous

i. The project authorities must strictly adhere to the stipulation made by the MP Pollution Control Board and the State Government.

ii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee (SEAC)

iii. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).

iv. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

v. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment

(Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

11. Case No 10853/2023 Shri Varun Kumar Gautam, Director, M/s Atisha Construction Private Limited, Village-Sarauli, Tehsil-Sihora, District-Jabalpur (MP)-482001, Prior Environment Clearance for Sarauli Laterite and Ochre Deposit in an area of 4.69 ha. (99999 cum per year) (Khasra No. 743/1, 743/2, 743/3, 744, 745, 746, 747, 748, 749), Village-Sarauli, Tehsil-Sihora, District-Jabalpur (MP) [523018] (EIA)

प्रस्तावित लेटेराईट खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 21/05/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भारद्धाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Varun Kumar Gautam, Director, M/s ATISHA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED, Village - Sarauli, Tehsil - Sihora, District - Jabalpur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	743/1, 743/2, 743/3, 744, 745, 746, 747, 748 & 749 (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.69 hectare.
स्थल	Village: Sarauli, Tehsil: Sihora, District: Jabalpur (M.P)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र पृ. क्रमांक 5128–29 दिनांक 27/04/23 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	फार्म्-1 के पार्ट-बी के सरल क्रमांक 21 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रशर प्रस्तावित नहीं।	
टॉर	सेक की 713वीं बैठक दिनांक 11/01/24 को अनुशंसित । सिया के पत्र क्रमांक 3175 दिनांक 01/03/24 के द्वारा Laterite and Ochre-99,999 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के Outward No:122467 दिनांक 27/03/25 द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 31/03/20230 तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Laterite and Ochre-99,999 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Laterite and Ochre-99,999 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1051 दिनांक 19/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 16.288 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी	

	का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1051 दिनांक 19/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1051 दिनांक 19/10/23 अनुसार 300 मीटर पर मानव बसाहट एवं 100 मीटर पर स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सरौली जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–2 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।
प्रस्तावित स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे हैं
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तरपूर्व दिशा– लीज क्षेत्र से लगा हुआ एक पक्का रोड है एवं 600 मी. की दूरी पर नहर स्थित है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक 1091 दिनांक 03/11/23 अनुसार उक्त खदान को अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया गया है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यो की समीक्षा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि लीज क्षेत्र पूर्व से खुदा हुआ है, जो माइन प्लान में स्पष्ट उल्लेखित है, लीज क्षेत्र में विद्मान वृक्ष काटे नहीं जावेगें एवं उत्तरपूर्व दिशा में लीज क्षेत्र से लगा हुआ एक पक्का रोड है जिसके संदर्भ में 100 मी. का सेटबेक प्रस्तावित किया है एवं इस क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Laterite and Ochre-99,999 घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 9.39 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 3.17 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 2.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि (रू.में)
ग्राम सरौली एकीकृत शासकीय उच्च माध्यमिक शाला में 5KW सोलर पैनल की व्यवस्था	2,50,000
ग्राम सरौली एकीकृत शासकीय उच्च माध्यमिक शाला में वाटर कूलर की व्यवस्था हेतु ।	10,000

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4,690 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

12. Case No 10039/2023 Shri Komal Singh Thakur, Lease Owner, R/o A-161, Siddharth Lake City, Anand Nagar, Raisen Road, District-Bhopal (MP)-462022, Prior Environment Clearance for Chandbad Kadeem Stone Quarry in an area of 3.300 ha. (75,662 cum per year) (Khasra No. 361/1/2, 361/2, 362/1), Village-Chandbad Kadeem, Tehsil-Berasia, District-Bhopal (MP) [534731] [DEIAA] (EIA)

Earlier in the SEAC meeting 662nd Dated 21.07.2023 TOR was recommended .

परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अजय मोहन, मेसर्स इन सिटू इंवयारो केयर, भोपाल द्वारा प्रस्तावित खदान का दिनांक 20/05/2025 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Komal Singh Thakur, Lease Owner, A-161, Siddharth Lake City, Anand Nagar, Raisen Road, Bhopal (MP)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	361/1/2, 361/2, 362/1 & 362/2 (निजी परियोजना प्रस्तावक के स्वामित्व की–नॉन फॉरेस्ट भूमि)	3.30 Ha.
स्थल	Village - Chandbad Kadeem, Tehsil- Berasiya, District Bhopal (MP)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 3828 दिनांक 10/04/17 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–1 Stone Quarry	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार सिंगल रो ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
Gram Panchayat NOC	The Gram Panchayat NOC issue on date 23/03/2017.	
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र लीज में स्थित है।	
नया/क्षमता विस्तार	नया	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया, भोपाल के पत्र 1298 दिनांक 23/09/17 द्वारा पत्थर–75,662 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–75,662 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–75,662 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1964 दिनांक 12/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 18.23 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है ।	

वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1964 दिनांक 12/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
त्हसीलदार की अनापत्ति	तहसीलदार, तहसील बैरसिया जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 99 दिनांक 20/03/17 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/ नहर/ ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा– कच्चा रोड़ 13 मीटर एवं दक्षिण पश्चिम में – शेड 400 मीटर
	पूर्व दिशा– कच्चा रोड़ 10 मीटर एवं फार्म हाऊस 357 मीटर, कच्चा रोड के सबंधं में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि यह हॉलेज रोड़ है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोड जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपठनीय है ।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यो की समीक्षा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि लीज क्षेत्र के दक्षिण दिशा में एक कच्चा रोड़ 13 मीटर पर है जो कि आम रास्ता नहीं है।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :–

- प्रस्तुत ईआईए में टॉर कम्पलाईन्स को बिन्दुवार ईआईए चेप्टर के अनुसार संदर्भ अंकित करें, टॉर के बिन्दुवार कम्पलाईन्स में नोटेड/रिक्त स्थान का पालन विवरण अंकित करें।
- स्पष्ट करें कि प्रस्तुत ईआईए में सरफेस वाटर क्वालिटी का conclusion रिजल्ट के आधार पर सही प्रतीत नहीं होता।
- कलस्टर मैनेजमेंट प्लान को प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बनाया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा शिल्टेशन पोन्ड के विवरण दिये जायें।
- डिया द्वारा जारी ईसी शर्तों का पालन – लीज एरिया के चारो ओर फेन्सिंग, वृक्षारोपण, गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टैंक का निर्माण, बैरियर जोन की स्थिति आदि संबंधित जियोटेग फोटोग्राफ, प्रमाणित दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें।

13. Case No 10651/2023 Ms. Priyanka Dwivedi, Owner, B-805, Jeevan Vihar, Kotra Road, District-Bhopal (MP)-462020, Prior Environment Clearance for Barigarh Stone Mine in an area of 2.50 ha. (150000 cum per year) (Khasra No. 349), Village-Barigarh, Tehsil-Gaurihar, District-Chhatarpur (MP) [520053] (EIA)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 21/05/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Smt. Priyanka Dwivedi, Owner, B-805, Jeevan Vihar Kotra Road, Bhopal (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	349 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.50 hectare.
स्थल	Village - Barigarh, Tehsil- Gaurihar, District – Chhatarpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 15249 दिनांक 11/11/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–1	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	फार्म्-1 के पार्ट-बी के सरल क्रमांक 21 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रशर प्रस्तावित नहीं।	
टॉर	सेक की 694वीं बैठक दिनांक 31/10/23 को अनुशंसित । सिया के पत्र क्रमांक 2286 दिनांक 18/12/23 के द्वारा 1,50,000 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर के Outward No 22642 दिनांक 22/04/2025 के द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 23.03.2030 तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–1,50,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–1,50,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 754 दिनांक 12/04/23 अनुसार 500 मीटर	

खदानें	की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 07.65 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 754 दिनांक 12 / 04 / 23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको संसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 754 दिनांक 12 / 04 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	नगर परिषद् बारीगढ़, जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 397 दिनांक 04 / 09 / 21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से निकाय को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि लीज क्षेत्र में 49 पेड़ लगे हुये हैं जिनमें से 40 पेड़ काटे जाने प्रस्तावित हैं
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– एक कच्चा रोड–10 मी., 40 मी. का सेटबेक प्रस्तावित किया है
	पूर्व दिशा– प्राकृतिक नाला लगभग 50 मी.
	पश्चिम दिशा– तालाब एवं आबादी >लगभग 700 मी. की दूरी पर
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 1026 दिनांक 15 / 05 / 23 अनुसार उक्त खदान को अद्यतन डीएसआर में सम्मिलित किया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29 / 07 / 22 (प्रकरण में 9261 / 2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04 / 08 / 22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक / पर्यावरणीय कार्यो की समीक्षा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि लीज क्षेत्र में 49 पेड़ लगे हुये हैं जिनमें से 40 बबूल एवं पलाश प्रजाति के हैं, जो लीज एरिया के कोर जोन में होने से काटे जाने प्रस्तावित

हैं। काटे जाने पेड़ों के एवज में 500 पेड़ अतिरिक्त लागाये जावेगें, लीज क्षेत्र से वनभूमि (पी–719) 370 मी. की दूरी पर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान कलस्टर मैनेजमेंट प्लान, ईएमपी योजना के साथ प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :–

- प्रस्तुत ईआईए में टॉर कम्पलाईन्स को बिन्दुवार ईआईए चेप्टर के अनुसार संदर्भ अंकित करें, टॉर के बिन्दुवार कम्पलाईन्स में नोटेड/रिक्त स्थान का पालन विवरण अंकित करें।
- लीज क्षेत्र चूँकि 19 मी. ऊँची पहाड़ी पर स्थित है अतः बर्षा का जल आस–पास के खेतों में न जाये इस हेतु ईएमपी योजना में बंडिंग/डाईक का प्रावधान समुचित बजट के साथ किया जावे तथा क्लस्टर मैनेजमेंट में इसका क्षेत्र अनुसार प्रावधान किया जाये।
- जन सुनवाई के दौरान उठाये गये बिन्दुओं का ईएमपी एवं सीईआर योजना में समिति के सुझाये अनुसार समावेश करें।

14. Case No 10827/2023 Ms. Astha Shrivastava, Lease Owner, 202, Apollo Pradise, Bawadiya Kalan, Gulmohar, Near Minal Enclave, District-Bhopal (MP)-462039, Prior Environment Clearance for Barigarh Stone Mine in an area of 2.65 ha. (150002 cum per year) (Khasra No. 349), Village-Barigarh, Tehsil-Gaurihar, District-Chhatarpur (MP) [520204] (EIA)

प्रस्तावित पत्थर खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 21/05/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	ASTHA SHRIVASTAVA, Lease owner, 202,Apollo Pradise, Bawadiya Kalan gulmohar, Near minal enclave , Bhopal (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	349 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.65 hectare.
स्थल	Village -Barigarh, Tehsil-Gaurihar, Distt.-Chhatarpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 15249 दिनांक 11/11/22 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	फार्म्-1 के पार्ट-बी के सरल क्रमांक 21 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित नहीं।	
टॉर	सेक की 710वीं बैठक दिनांक 05/01/24 एवं 733वीं बैठक दिनांक 28/03/24 को अनुशंसित । सिया के पत्र क्रमांक 591 दिनांक 15/05/24 के द्वारा पत्थर-1,50,002 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर के Outward No:22643 दिनांक 22/04/2025 द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 23.03.2030 तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–1,50,002 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–1,50,002 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र	

परिधि में अन्य खदानें	क्रमांक 755 दिनांक 12/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 07.80 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 755 दिनांक 12/04/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 755 दिनांक 12/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	नगर परिषद् बारीगढ़ जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 397 दिनांक 04/09/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से नगर परिषद् को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि लीज क्षेत्र में 49 पेड़ लगे हुये हैं
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– एक कच्चा रोड– 50 मी.
	पूर्व दिशा– प्राकृतिक नाला लगभग 60 मी.
	पश्चिम दिशा– तालाब एवं आबादी >लगभग 700 मी. की दूरी पर
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 1025 दिनांक 15/05/23 अनुसार उक्त खदान को अद्यतन डीएसआर में सम्मिलित किया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यो की समीक्षा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि लीज क्षेत्र में 50 पेड़ लगे हुये हैं जिनमें से 30 पेड़ लीज एरिया के कोर जोन में एवं 20 पेड़ बैरियर जोन में स्थित है। कोर जोन के 30 पेड़ काटे जाने प्रस्तावित हैं काटे जाने पेड़ों के एवज में 300 पेड़ अतिरिक्त लागाये जावेगें। जो कि बबूल एवं पलाश प्रजाति के हैं प्रस्तुतीकरण के दौरान कलस्टर मैनेजमेंट प्लान, ईएमपी योजना के साथ प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :–

- प्रस्तुत ईआईए में टॉर कम्पलाईन्स को बिन्दुवार ईआईए चेप्टर के अनुसार संदर्भ अंकित करें, टॉर के बिन्दुवार कम्पलाईन्स में नोटेड/रिक्त स्थान का पालन विवरण अंकित करें।
- लीज क्षेत्र चूँकि 19 मी. ऊँची पहाड़ी पर स्थित है अतः बर्षा का जल आस–पास के खेतों में न जाये इस हेतु ईएमपी योजना में बंडिंग/डाईक का प्रावधान समुचित बजट के साथ किया जावे।
- जन सुनवाई के दौरान उठाये गये बिन्दुओं का ईएमपी एवं सीईआर योजना में समिति के सुझाये अनुसार समावेश करें।

15. Case No P2/1332/2025 Shri Arvind, Ujnethi Flag Stone, Khanda/Dhoka, Boulder & M-Sand Quarry, R/O - pandapura , Baghraj Ward, Sagar City District Sagar, Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area (Flagstone-6030 cum per annum Khanda/Dhoka-540 cum per annum Boulder-540 cum per annum & M-Sand-990 cum per annum (Khasra No. 781/2, 765/1, 780, 792/2, 766/1, 778, 779, 768, 769, 770, 771, 774, 775/1) Village-Ujnethi, Tehsil- Shahgrah, District- Sagar (M.P.).. (529892) (B2) Fresh

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति के पुर्णमूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 21/05/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार सुश्री स्वाति नामदेव, कोर्डीनेटर, मेसर्स ए.एस.जी इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि, दिल्ली. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Arvind, Owner, R/O - pandapura , Baghraj Ward, Sagar City District Sagar M.P.).	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	781/2, 765/1, 780, 792/2, 766/1, 778, 779, 768, 769, 770, 771, 774, 775/1 (निजी/सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.00 hectare.
स्थल	Village- Ujnethi, Tehsil- Shahgrah, District- Sagar (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 250 दिनांक 18/12/25 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	फार्म्-1 के पार्ट-बी के सरल क्रमांक 21 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित नहीं।	
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर/एमसेण्ड प्लांट प्रस्तावित नही है ।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 31/03/30 तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लेगस्टोन (फर्शीपत्थर), खण्डा/ढोका, बोल्डर एवं एम–सेण्ड–8100 घनमीटर/वर्ष (फ्लेगस्टोन (फर्शीपत्थर)–6030 घनमीटर/वर्ष, खण्डा/ढोका–540 घनमीटर/वर्ष, बोल्डर–540 घनमीटर/वर्ष एवं एम–सेण्ड – 990 घनमीटर/वर्ष) हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 8100 घनमीटर/वर्ष (फ्लेगस्टोन (फर्शीपत्थर)–6030 घनमीटर/वर्ष, खण्डा/ढोका–540 घनमीटर/वर्ष, बोल्डर–540 घनमीटर/वर्ष एवं एम–सेण्ड – 990 घनमीटर/वर्ष) है।	

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 259 दिनांक 20/2/25 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण/ एसईजेड से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 259 दिनांक 20/2/25 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 259 दिनांक 20/2/25 अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 259 दिनांक 20/2/25 अनुसार 300 मीटर की दूरी नदी/नाला एवं कच्चा रास्ता स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में स्थित नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत उजनेठी जिला सागर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-4 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र के बैरियर जोन में कई पेड प्रस्तावित है। जिन्हें काटा नही जायेगा
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– लीज क्षेत्र के उत्तर दिशा में कच्चा रोड है जो लगभग 400 मीटर की दूरी पर है।
	दक्षिण दिशा- लीज क्षेत्र के दक्षिण दिशा में लगभग 300 मीटर दूरी है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोडा जावेगा।

During presentation PP submitted that previously, this mine was sanctioned to Smt. Sarika Jain W/o Shri Amit Jain, R/o- Rampura ward, Sagar (M.P.) with the 1.00 Hact. in khasra no. (780, 765/1, 766/1, 775/2) Private Land and another mine was sanctioned to Mr. Amit Jain S/o- Shri Suresh Chandra Jain, R/o- Rampura ward, Sagar(M.P.) with the 4.930 Hact. In khasra no. (758, 781, 792) Private Land. The mines were sanctioned for 10 Years from 2017 to 2027. Both the mines was run

from 2017-2023. After Some time both mine are surrendered with the letter no. 1534/Khanij/2024 Date-30/12/2024 and Second Mine Letter No. 1535/Khanij/2024 Date – 30/12/2024. This is the reason why the mine area is shown dug up, both mine's surrender letter are presented.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता– फलेगस्टोन (फर्शीपत्थर) –8100 घनमीटर/वर्ष, खण्डा/ढोका–6030 घनमीटर/वर्ष, बोल्डर– 540 घनमीटर/वर्ष एवं एम–सेण्ड–990 घनमीटर/वर्ष

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 8.31 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 1.60 लाख प्रति वर्ष ।

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 2.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि (रू.में)
सी.ई.आर मद से 2,70,000 की राशी शासकीय माध्यमिक शाला उजनेठी मे छात्र/छात्राओं के लिये 60 कुर्सी–टेबल के सेट हेतु जमा की जावेगी।	2,70,000

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1,600 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

16. Case No P2/1333/2025 Nepal Singh, Gram Sakarra, post edour teh esagarh, Sakarra, Ashok Nagar, Madhya Pradesh – 473335, Prior Environment Clearance for Proposed Flag Stone quarry area is 1.00 hectares. Flagstone - 1,500 M3/Year, at Khasra no. – 419, Village- Sakarra, Tehsil- Isagarh, Distt. – Ashoknagar (M.P.). [518626] (B2).

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 21/05/2025 को परियोजना प्रस्तावक श्री नेपाल सिंह एवं उनके पर्यावर्णीय सलाहकार Smt. Swati Namdeo M/s AGS Environmental Services Pvt. Ltd., Delhi उपस्थित हुई और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना की रूपरेखा

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	**Shri Nepal Singh, Gram Sakarra, Post – Edour, Tehsil - Esagarh, Sakarra, Ashok Nagar, Distt. - Ashok Nagar (M.P.) – 473335,** Prior Environment Clearance for Proposed Flag Stone quarry area is 1.00 hectares. Flagstone – 1,500 M^3/Year, at Khasra no. – 419(Govt. Land), Village - Sakarra, Tehsil - Isagarh, Distt. –Ashoknagar(M.P.). **SIA/MP/MIN/518626/2025.** **B2 Fresh Case.**	
परियोजना का खसरा नं. /लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.– 419,	एरिया – 1.00 ha., (Govt. Land),
परियोजना स्थल	Village - Sakarra, Tehsil - Isagarh, Distt. – Ashoknagar (M.P.).	
Description of Project	The proposed Flag Stone quarry area is 1.00 hectares. Flag stone mining capacity shall be Flagstone 1.500 M3/Year, mode of The excavation is opencast semi-mechanized. The total available mineable reserve is 23,918M3 proposed excavation is to be done up to a depth of 15M with 1,500M3 stone production annually.	
सैंधातिक सहमति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **अशोकनगर** के पत्र क0. 2812 दिनांक 05/03/2024.	
परियोजना की श्रेणी	**बी–2.**	
जल/वायु सम्मति	PCB ID : 168357, Consent No:CTE-129567, Consent to Establish valid upto 31/03/2030.	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	NA.	
उत्पादन क्षमता	Flagstone – 1,500 M^3/Year,	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **अशोकनगर** के एकल प्रमाण–पत्र कमांक 270 दिनांक 27/06/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत नही है जिनका कुल रकबा 1.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	

परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **अशोकनगर** के एकल प्रमाण–पत्र कमांक 270 दिनांक 27/06/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **अशोकनगर** के एकल प्रमाण–पत्र कमांक 270 दिनांक 27/06/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि संबंधी जानकारी नही है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत – सकर्रा, जिला – **अशोकनगर** का ठहराव प्रस्ताव क0. 03 दिनांक 22/08/2022 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में झाड़ियॉ लगी हैं जो नहीं काटी जावेगी।
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर दिशा– .कच्चा रोड 33 मी., 20 मी. का सेटबैक प्रस्तावित है एवं उत्तर एवं उत्तर–पश्चिम दिशा में क्रमशः 100 एवं 139 मी. की दूरी पर कुछ कच्चे घर हैं।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. – 44 के सरल कमांक – 34 पर दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Flagstone–1,500 M^3/Year,
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 3.48 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1. 47 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रू0. में)
ग्राम सकर्रा की शासकीय प्राथमिक शाला की रखरखाव कार्य हेतु 1,00,000 की राशि प्रदान की जावेगी। एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्य पूर्ण करवा कर प्रधानाचार्य द्वारा कार्यपूर्ण पत्र प्राप्त किया जायेगा।	1,00,000/-
योग	1,00,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

<u>अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा के अन्य बिन्दु :-</u>

- Member Secretary SEAC informed that fee is being deposited at SEIAA Secretariate, so adequacy of fee shall be verified by SEIAA Secretariate.
- The project proponent shall comply the MOEF&C's O.M. dated 24 July 2024 for ensuring plantation.
- The PP shall obtain necessary permissions from MPPCB as per prevailing Water, Air Acts, and Member Secretary shall farward the case to MPPCB for necessary action till arrangement are not available on Parivesh Portal.

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

(राकेश कुमार श्रीवास्तव)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. The project proponent shall comply the MOEF&C's O.M. dated 24 July 2024 for ensuring plantation.
38. **लीज क्षेत्र के अंदर में केवल क्रेशर /एम–सेंड प्लांट स्थित है, परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।**
    - खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
    - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
39. **कशर अथवा एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित नही है ,परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।**
    - परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नही है, अतः लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट/एम. सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नही दी जा सकेगी।
    - खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
    - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।

40. **यदि आवंटित खनन पट्टा भू–स्वामी की सहमति /अनुबंध पर हो तो परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।**

1. <u>**क्षतिपूर्ति के संबंध मेंः–**</u>
    - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियो को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
    - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तो का पालन भू–प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।

<u>Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:</u>

<u>Annexure- 'B'</u>

<u>Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*</u>

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.

9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE’s. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine’s site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled “Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area”.
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner’s Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    d. Minable Potential of sand mine.
    e. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    f. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA’s instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.

i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37ए As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river…….bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.
38. The project proponent shall comply the MOEF&C's O.M. dated 24 July 2024 for ensuring plantation.
39. विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
40. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।